978/968 जनसत्ता पृ० (9) 16/8/2015

कृषि मंत्रालय का नाम अब 'कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय'

नई दिल्ली, 15 अगस्त (भाषा)। किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सात दशक पुराने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर 'कृषि व किसान कल्याण' मंत्रालय कर दिया गया है। यह घोषणा शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

लालकिले की प्राचीर से 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में मोदी ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि सरकार फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। कृषि क्षेत्र समग्र विकास के लिए किसानों के कल्याण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर 'कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय' करेगी।

आजादी से पहले भारत में राजस्व, कृषि व वाणिज्य विभाग था जिसकी स्थापना जून 1871 में हुई थी। इसके बाद 1881 में इसे पुनर्गठित कर राजस्व व कृषि विभाग को अलग कर दिया गया लेकिन 1923 में शिक्षा और स्वास्थ्य को इसमें शामिल कर – शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि – कर दिया गया।

इसके बाद 1945 में इसे तीन अलग अलग विभागों कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में बांट दिया गया। कृषि विभाग को अगस्त 1947 में कृषि मंत्रालय में तब्दील किया गया। वर्तमान में कृषि मंत्रालय का कार्यभार राधामोहन सिंह के पास है और मंत्रालय पर फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए नीतियां तैयार करने का जिम्मा है। मंत्रालय 20 से अधिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करता है।

उपभोक्ता मामलों, खाद्य व सार्वजनिक वितरण के लिए एक अलग मंत्रालय है जिसका कार्यभार राम विलास पासवान के पास है। इस मंत्रालय पर अनाज की खरीद और राशन की दुकानों के जरिए आपूर्ति का जिम्मा है।

मोदी ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को बिजली और सिंचाई की सुविधा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है।

उन्होंने कहा 'हमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।' मोदी ने कहा कि हर बूंद से ज्यादा से ज्यादा फसल प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराएगी।

मोदी ने कहा कि सरकार ने 100 फीसद नीम परत चढ़े यूरिया उत्पादन की मंजूरी दी है ताकि इस उर्वरक का रासायनिक उद्योग में दुरुपयोग न हो। साथ ही किसानों से कहा कि वे सिर्फ नीम लेप वाले यूरिया का ही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि नीम के लेप वाले यूरिया को पेश करने से सबसिडीशुदा यूरिया के गैर कृषि उपयोग को खत्म करने में मदद मिली है।

मोदी ने कहा कि सरकार पूर्वी भारत समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बंद पड़े यूरिया संयंत्र के पुनरुद्धार की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगले पांच साल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की घोषणा की है।

फिलहाल 14.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि का उपयोग खेती के लिए होता है जिसमें सिर्फ 45 फीसद कृषि भूमि सिंचाई सुविधा वाली है। इसके अलावा एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी पेश की गई है जिसके तहत केंद्र अगले तीन साल में 14 करोड़ किसानों को लक्ष्य किया जाएगा ताकि उर्वरक के अत्यधिक उपयोग पर नियंत्रण किया जा सके।

भारत का अनाज उत्पादन 2014-15 में 5.25 फीसद घटकर 25.11 करोड़ टन रह गया जो इससे पिछले साल 26.504 करोड़ टन था।

सुनीता गुप्ता
17/8/15
प्रभारी पत्रिका एवं समाचार पत्र अनुभाग

प्रति लिपि :
1. निजी सचिव : निदेशक कार्यालय
2. निजी सचिव : संयुक्त निदेशक (प्रसार)
3. निजी सचिव : संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)
4. निजी सचिव : संयुक्त निदेशक/अधिष्ठाता (शिक्षा)
5. प्रभारी : पी.एम.यू.
6. प्रभारी : कैटेट
7. प्रभारी : ए.के.एम.यू.